आरक्षित निर्णय

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

विशेष अपील संख्या 88/ 2012

भगवान महादेव ट्रस्ट .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थी(गण)

श्री ए. एस. रावत, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री चरणजीत कौर द्वारा सहायता प्राप्त, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता।

श्री जे.पी. जोशी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य के प्रत्यर्थी(गण) के लिए।

फैसला सुरक्षितः 01.12.2018

निर्णय दिया गयाः 08.01.2019

संदर्भित मामलेः

1. (2010) 11 एससीसी 242

2. (2014) 13 एस. सी. सी. 721

3. (2012) 11 एससीसी 370

4. (2011) 5 एससीसी 553

5. (2012) 1 एस. सी. सी. 792

6. (2011) 4 एससीसी 769

7. (2011) 9 एससीसी 164

8. ए.आई.आर. (1954) एससी 119

9. ए.आई.आर. (1951) एससी 41

10. (1995) सप।(1) एससीसी 596

11. (2003) 5 एस. सी. सी. 622

12. (2003) 7 एससीसी 336

13. (2012) 11 एससीसी 370

14. ए. आई. आर 1967 एस. सी 1081

15. (1971) 3 एससीआर 871

16. (1977) 1 एस. सी. सी 133

17. (1980) 2 एस. सी. सी. 471

18. (1984) 4 एससीसी 308

19. (1986) 4 एससीसी 251

20. (1993) 2 एससीसी 84

21. (1996) 2 एस. सी. सी. 549

22. (1996) 11 एससीसी 462

23. (1998) 6 एससीसी 1

24. (2004) 8 एससीसी 14

25. (2005) 7 एस. सी. सी 627

26. (2008) 12 एस. सी. सी. 418

27. (2009) 10 एससीसी 115

28. (2009) 10एससीसी689

29. (1973) 2 एससीसी 337;

30. (1993) 4 एससीसी 255;

31. (2002) 4 एससीसी 160

32. ए. आई. आर. 1975 एससी 1767

33. ए. आई. आर. 2017 एससी 854

34. 1993 (4) एससीसी 369

35. 1995 (6) एससीसी 31

36. (2017) 12 एससीसी 840

37. (2014) 14 एससीसी 127

कोरमः **माननीय रमेश रंगनाथन, सी.जे.,**

माननीय आलोक सिंह, जे.

रमेश रंगनाथन, सी.जे.

यह अपील रिट याचिका (एम/एस) सं. 1131/ 2007 दिनांक 02.05.2012 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध की जाती है।अपीलकर्ता ने यहाँ उक्त रिट याचिका दायर की जिसमें प्रथम परमादेश द्वारा क्रमशः जारी अधिसूचना और घोषणा दिनांक 20.05.2003 और 16.06.2003 सरशियोरेराई करने के लिए प्रमाण पत्र की रिट की मांग की गई; और प्रतिवादी को सम्पति का कब्जा उन्हें सौंपने का निर्देश देने के लिए एक अनिवार्य रिट, और विषय सम्पति के उनके सुचारू और शांतिपूर्ण कब्जे में कोई बाधा पैदा न करने के लिए।

2. तथ्य, आवश्यक सीमा तक, यह है कि अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता 30.05.1997 पर बनाया गया एक पंजीकृत न्यास है।इसने हाउस नं. 23, लक्ष्मी रोड, देहरादून जिसे दिनांक 01.12.1999 के आदेश के अनुसार अपने नाम में परिवर्तित किया गया था।यह अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता से मामला है कि चूंकि वे शैक्षिक गतिविधियों को प्रदान करने और बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, और राय विश्वविद्यालय चला रहे थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी रोड पर 4061.33 वर्ग मीटर की विषय सम्पति खरीदी थी। मीटर, 01.04.1999 पर रुपये के लिए एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से। 50.00 लाख; उन्होंने रु। उक्त सम्पति के पंजीकरण के लिए 3 लाख रुपये; एक सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण संस्थान चलाने के लिए और डिप्लोमा या स्नातक सीमा पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले एक नए तकनीकी संस्थान को शुरू करने के लिए विषय भूमि खरीदी गई थी; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपनी सेर्यवाही दिनांक 2 द्वारा, विद्या सम्बन्धी वर्ष के लिए उपरोक्त पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए अनुमोदन देने के उनके अनुरोध को अस्वीसेर कर दिया; उन्हें सूचित किया गया कि उनके आवेदन पर अगले वर्ष के लिए विचार किया जा सकता है, और उन्हें आवश्यक जानसेरी 18.08.2000 द्वारा प्रस्तुत करनी चाहिए; जबकि मामले इस प्रसेर थे, उत्तरांचल राज्य से गठन 09.11.2000 पर किया गया था, U.P के अनुसार। राज्य की राजधानी के रूप में देहरादून के साथ पुनर्गठन अधिनियम, 2000; प्रतिवादी द्वारा विषय सम्पति से अधिग्रहण करने पर, अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता ने रिट याचिसे दायर की (एम /बी) उक्त मांग को चुनौती देते हुए 2002 का 165; और इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी को या तो 10 दिनों के भीतर अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता को सम्पति का कब्जा सौंपने या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (जिसे इसके बाद "1894 अधिनियम" कहा जाता है) के से उसे हासिल करने का निर्देश दिया।

3. इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, रिट याचिका (एम/बी) सं। वर्ष 2002 का 165 दिनांक 06.05.2003, 1894 के अधिनियम की खंड 4 के से 20.05.2003 पर एक अधिसूचना जारी की गई थी, और उक्त अधिनियम की खंड 5-ए की आवश्यकता के साथ उक्त अधिनियम की खंड 17 (4) के से तात्कालिकता खंड को लागू

किया गया था। इसके बाद 1894 के अधिनियम की खंड 6 के से 16.06.2003 पर एक घोषणा जारी की गई।ये कार्यवाही दिनांक 20.05.2003 (जिसके द्वारा 1894 अधिनियम की धारा 17 (4) के साथ पठित धारा 4 (1) के से एक अधिसूचना जारी की गई थी), और बाद में जारी की गई घोषणा, जो दिनांक 16.06.2003 के 1894 अधिनियम की धारा 6 के से जारी की गई थी, जिखंड रिट याचिका (एम/बी) संख्या में चुनौती दी गई थी। 2003 का 607 जिखंड बाद में रिट याचिका (एम/एस) सं। 2007 का 1131।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर जवाबी शपथ पत्र में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि विभाग ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात 14.05.2001 पर इमारत का कब्जा ले लिया; वित्त विभाग के नियंत्रण में कई कार्यालय वहां चल रहे थे; विषय सम्पति को पहले U.P की धारा 3 के से अधिग्रहित किया गया था। आवास और अनुरोध अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "1947 अधिनियम"); इस न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका (एम/बी) सं। 2002 का 165 दिनांक 06.05.2003, विषय भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी; निदेशक, ट्रेजरी और वित्त खंडवा, उत्तरांचल, देहरादून द्वारा विषय भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया गया था, उनके पत्र दिनांक 08.05.2003 द्वारा; विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, देहरादून ने निदेशक, ट्रेजरी और वित्त खंडवा, उत्तरांचल, देहरादून को कुल अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए सूचित किया; परिणामस्वरूप 1 लाख रुपये जमा किए विद्वान; इसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट ने 1894 के अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 4 के से कार्यवाही जारी की, क्योंकि अधिग्रहण जनहित में था; विषय सम्पति जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थी, और खाली और अप्रयुक्त पड़ी थी; इसलिए इस आशय का एक नोटिस जारी किया गया था, जो समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, और राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया था; इसके पश्चात नोटिस जारी किए विद्वान थे जो 1894 के अधिनियम की धारा 4,6 और 9 के से जारी किए विद्वान थे, और इसके से बनाए विद्वान नियमों के अनुसार प्रकाशित किए विद्वान थे; वित्त विभाग के कार्यालयों के लिए भवन का उपयोग जनहित में है; और, क्योंकि सम्पति का अधिग्रहण करने की तात्कालिकता थी, इसलिए 1894 के अधिनियम की धारा 17 (4) के से प्रक्रिया को अपनाना अवैध नहीं कहा जा सकता है।

5. इसके जवाब में अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता ने अपने जवाबी शपथ पत्र में तर्क दिया कि, एक सार्वजनिक कार्यालय का पता लगाने के उद्देश्य खंड, अधिकारी अधिग्रहण को मात्र विषय परिसर तक ही सीमित कर सकते थे; पूरी भूमि का अधिग्रहण करना आवश्यक नहीं था; राज्य द्वारा पूरी भूमि का अधिग्रहण अवैध था, और 1894 के अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था; और, 1894 के अधिनियम की धारा 3 (एफ) को देखते हुए, विधायिका के पास सार्वजनिक कार्यालय का पता लगाने के लिए खुली भूमि का अधिग्रहण करने की शक्ति नहीं थी।

6. प्रतिवादी द्वारा एक पूरक शपथ पत्र दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि देहरादून में सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के लिए आवास की भारी कमी को देखते हुए सरकारी कार्यालयों की स्थापना के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

7. अपील के से आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता की ओर खंड और प्रतिवादी की ओर खंड उद्धृत कई फैसलों का उल्लेख करने के बाद कहा कि विषय सम्पति पहले खंड ही मई, 2001 खंड राज्य सरकार के उपयोग में थी; यह तथ्य पक्षों द्वारा विवादित नहीं था; विषय सम्पति पहले 1947 अधिनियम की धारा 3 के से मांगी गई थी; विवादित सम्पति पर राज्य सरकार का कब्जा स्थापित किया विद्वान था; सरकारी

कार्यालय विषय भवन में काम कर रहे थे; उत्तरांचल राज्य के निर्माण के पश्चात देहरादून को राज्य की अस्थायी राजधानी के रूप में घोषित किया विद्वान था; विषय सम्पति वित्त विभाग के नियंत्रण में कार्यालयों के उपयोग के लिए अधिग्रहित की गई थी, और ये कार्यालय विषय भवन में काम कर रहे थे; जबकि इसके द्वारा तर्क दिया विद्वान था

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि विषय भूमि की मांग जनहित में थी; जबकि अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता के पास दिल्ली और अन्य स्थानों पर शैक्षणिक संस्थान थे, और वह देहरादून में एक नया तकनीकी संस्थान खोलना चाहता था, नए राज्य के निर्माण के पश्चात सार्वजनिक सेर्यालयों से उद्घाटन अधिक महत्वपूर्ण था और बड़े पैमाने पर जनता के लिए अधिक फायदेमंद था; राज्य सरसेर ने वित्त विभाग के नियंत्रण में सेम करने वाले विभिन्न सेर्यालयों से पता लगाने के लिए विषय भूमि से अधिग्रहण विद्वान था; और अधिग्रहण जनहित में था।

9. इस सवाल पर कि क्या अधिनियम की धारा 5-ए के से जांच को समाप्त करने के लिए 1894 के अधिनियम की धारा 17 (4) के प्रावधानों को लागू करने की कोई तात्कालिकता आवश्यक थी, या क्या तात्कालिकता प्रश्न को अस्तित्व में न होने वाले तथ्यों पर या दिमाग का उपयोग न करने पर या दुर्भावना के आधार पर लागू किया विद्वान था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि राज्य ने वर्ष 2001 में विवादित भवन पर कब्जा कर लिया था; इखंड पहले 1947 के अधिनियम के प्रावधानों के से अधिग्रहित किया विद्वान था; अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता ने लिखित याचिका (एम/बी) नं. 2002 का 165; अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता की ओर खंड, विषय सम्पति में स्थित राज्य कार्यालयों के कब्जे के लिए धमकी दी जा रही थी; इस न्यायालय ने 2002 की रिट याचिका (एम/बी) में अपने आदेश द्वारा प्रतिवादी को या तो 10 दिनों के भीतर विवादित सम्पति का कब्जा सौंपने या 1894 अधिनियम के से उखंड हासिल करने का निर्देश दिया था; ऐसी परिस्थितियों में, राज्य ने 1894 अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत धारा 17 (4) के प्रावधानों को लागू करते हुए, 1894 अधिनियम की धारा 5-ए के से जांच के साथ एक अधिसूचना जारी की थी; इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता था कि 1894 अधिनियम धारा 17 (4) के प्रावधानों को लागू करने की कोई वास्तविक और वास्तविक आवश्यकता नहीं थी और विवादित संपत्ति का कब्जा नहीं प्राप्त होने पर अपीलकर्ता/ याचिकाकर्ता न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (एम/बी) 165/ 2002 मे पारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य कब्जा प्रदान करेगा ।

10. इसके पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता की इस प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया कि, विषय सम्पति का अधिग्रहण करने के पश्चात राज्य ने इसके लिए रु। निदेशक, कोषागार अग्रेतर वित्त सेवाओं के कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए 1,51,79, 000/- रुपये की अतिरिक्त राशि। 53,35,000/- निदेशक, लेखा अग्रेतर पात्रता के कार्यालयों के निर्माण के लिए खर्च किया विद्वान था; अग्रेतर रु। 4,23,63, 000/- वाणिज्यिक कर विभाग के लिए खर्च किया विद्वान था।

11. **आनंद सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1** मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने पश्चात विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि मामले के तथ्य **आनंद सिंह 1** मामले के लगभग समान थे; एक पुरस्कार दिया विद्वान था, और राज्य ने रुपये खंड अधिक की राशि खर्च की है। सरकारी कार्यालयों के

निर्माण के लिए ₹1 करोड़; और इसलिए, अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं था, भले ही यह माना विद्वान हो कि धारा 5-ए के से जांच का वितरण उचित नहीं था।

12. इसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने मत दी कि अस्तित्व और तात्सेलिकता सरसेर की व्यक्तिपरक संतुष्टि से विषय है; यह अदालतों के लिए एक अपीलीय अदालत के रूप में जांच करके संतुष्टि की औचित्य या शुद्धता की जांच करने के लिए खुला नहीं था; न्यायालय की शक्ति मात्र इस आधार पर सीमित थी कि निर्णय गैर-मौजूद तथ्यों पर या दिमाग से उपयोग न करने के सेरण लिया विद्वान था या यह दुर्भावना सीमा दूषित था; वर्तमान मामला गैर-मौजूद तथ्यों या दिमाग से उपयोग न करने या दुर्भावनापूर्ण इरादे से मामला नहीं था; अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता की ओर सीमा आग्रह किया विद्वान था कि सम्पति निदेशक के आदेशों पर किया विद्वान था।

13. अपीलार्थी-लिखित याचिसेकर्ता के इस तर्क पर कि विषय भूमि से अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है, 1894 के अधिनियम की धारा 3 (च) को देखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि धारा 3 (च) के खंड (viii) को अलग खंड नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन इखंड 1894 के अधिनियम की धारा 3 (ए) के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो 'भूमि' को परिभाषित करता है; 'भूमि' अभिव्यक्ति में भूमि खंड उत्पन्न होने वाले लाभ शामिल हैं, और पृथ्वी खंड जुड़ी चीजें या पृथ्वी खंड जुड़ी किसी भी चीज़ को स्थायी रूप खंड बांधा विद्वान है; 1894 के अधिनियम की धारा 3 (ए) के संदर्भ में भूमि से अधिग्रहण किया जा सकता है, साथ ही उस पर एक आवास भी खड़ा हो सकता है; राज्य ने बड़े पैमाने पर जनता के हित में विवादित सम्पति से अधिग्रहण किया था; और यह वास्तविक और प्रमाणित था।

14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अग्रेतर कहा कि चूंकि इस न्यायालय ने रिट याचिका में अपने आदेश में (एम /(ख) नहीं। 2002 के 165 ने राज्य को 10 दिनों के भीतर सम्पति का कब्जा सौंपने या उसी का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि 10 दिनों के भीतर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था, तो राज्य को सम्पति के कब्जे से बेदखल करने के लिए उत्तरदायी होगा; अपीलकर्ता रिट याचिकाकर्ता का तर्क कि चूंकि राज्य के कब्जे में था, इसलिए तत्काल खंड का आह्वान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और जांच को समाप्त करने के लिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता था; अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता तथ्यों का अस्तित्व न होने या मन का उपयोग न करने या विषय सम्पति का अधिग्रहण दुर्भावना से दूषित होने को स्थापित करने में विफल रहा था; और अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को नहीं किया गया था।तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की गई।

15. हमारे समक्ष अपीलकर्ता-लिखित प्रतिवादी की ओर खंड उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अवतार सिंह रावत प्रस्तुत करेंगे कि 1894 के अधिनियम की धारा 5-ए के से जांच में भूमि मालिक का अपनी आपत्तियां दर्ज आदेश का अधिकार एक मौलिक अधिकार है; यह भूमि मालिक के लिए खुला है कि वह 1894 के अधिनियम की धारा 4 (1) के से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किए विद्वान अधिग्रहण की धारा 5-ए जांच में आपत्तियां उठाए; जैखंड कि 1894 के अधिनियम की धारा 17 (4) के से तात्कालिकता खंड का आह्वान, भूमि मालिक को धारा 5-ए के से आपत्तियां दर्ज आदेश के अपने मूल्यवान अधिकार खंड वंचित करता है, यह मात्र असाधारण परिस्थितियों में और वास्तविक तात्कालिकता के मामलों में, 1894 की धारा 17 (4) के से तात्कालिकता खंड हो सकता है। दिनांक 2 के 165 में मात्र प्रतिवादी को दस दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता थी; भूमि अधिग्रहण का अर्थ मात्र 1894 के अधिनियम की धारा 4 (1) के से एक अधिसूचना जारी करना होगा; क्योंकि अपीलकर्ता-लिखित

याचिकाकर्ता मात्र सक्षम दीवानी अदालत के समक्ष मुकदमा दायर करके विषय भूमि के वितरण की मांग कर सकता था, इसलिए प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 17 (4) के से तत्काल खंड का आह्वान करने या 1894 के अधिनियम की धारा 5-ए के से जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को धारा 5-ए के से अपनी आपत्तियां दायर करने का एक ठोस अधिकार है, और जैसा कि यह स्पष्ट है कि धारा 5-ए के से जांच को समाप्त करने के लिए धारा 17 (4) के से तत्काल खंड का आह्वान करना आवश्यक है। 2002 का 165 दिनांक <आई. डी. 1>, या तो विषय भूमि का कब्जा अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता को सौंपना था या 1894 अधिनियम के से अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ना था; इसका मात्र यह अर्थ था कि 1894 अधिनियम की धारा 4 (1) के से एक अधिसूचना आदेश के दस दिनों के भीतर जारी करने की आवश्यकता थी, और उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) के से तात्कालिक खंड का आह्वान नहीं करना था; तथ्य यह है कि, तात्कालिकता की कमी के बावजूद, धारा 5-ए के से जांच को समाप्त कर दिया विद्वान था, जो उत्तरदाताओं की ओर खंड दिमाग का उपयोग न करने का खुलासा करेगा; यह 1894 अधिनियम की धारा 6 के से घोषणा को अपास्तने के लिए पर्याप्त होगा; और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इन तथ्यों पर विचार नहीं करने और ऐप को अस्वीकार करने में गलती की थी।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2; राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य 3; राधेश्याम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य *; और रघबीर सिंह सहरावत बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 5 पर भरोसा करेंगे।

17. दूसरी ओर उत्तराखंड राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जोशी प्रतिवादी की कार्रवाई को उचित ठहराने की कोशिश करेंगे और प्रस्तुत करेंगे कि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (एम/एम) में आदेश पारित किए जाने से बहुत पहले 1947 के अधिनियम के से इस विषय भूमि का कब्जा लिया विद्वान था। 2002 का 165 दिनांक 06.05.2003 इस न्यायालय के दिनांक06.05.2003 के आदेश में प्रतिवादी को विषय भूमि के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता थी; तब तक प्रतिवादी द्वारा विषय भूमि पर भवनों का निर्माण पहले ही किया जा चुका था; उनके अस्तित्व में इस अदालत के कब्जे के वितरण का निर्देश देने की संभावना थी, क्योंकि रिट याचिका (एम/बी) नं. 2002 का 165 अभी भी लंबित था, और पश्चात में दिनांक 1 के आदेश द्वारा निपटाया विद्वान था; इसलिए, प्रतिवादी के पास विषय भूमि का कब्जा लेने के लिए 1894 के अधिनियम की धारा 17 (4) के से तात्कालिक खंड को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था; विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपील के से आदेश पारित होने खंड 8 साल खंड अधिक समय पहले एक पुरस्कार पारित किया विद्वान था; अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को भी पुरस्कार के संदर्भ में मुआवजे की पेशकश की गई थी; अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को, यदि वे इतने व्यथित थे, तो 1894 के अधिनियम की धारा 18 के से संदर्भ की मांग करने खंड और मुआवजे में वृद्धि की मांग करने के लिए संदर्भ अदालत का दरवाजा खटखटाने खंड कुछ भी नहीं रोकता था; क्योंकि वे ऐसा करने में विफल रहे, यह इस समय की दूरी पर पूरी तरह खंड अनुचित होगा। 2007 का 1131; और इस न्यायालय के लिए यह पूरी तरह खंड असमान होगा कि अब धारा 6 की घोषणा को अपास्त करने के लिए अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता के अनुरोध मान लेना किया जाए, क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि पुरस्कार को अलग रखने की आवश्यकता होगी, धारा 4 (1) के से अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी (1894 अधिनियम की धारा 11ए को देखते हुए), और प्रतिवादियों को अब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013

(संक्षेप में "2013 अधिनियम") में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के से नए सिरे खंड कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता होगी।

18. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एम/एस) नं. 2007 का 1131, इस आधार पर कि खंड 17 (4) में तात्कालिकता खंड को लागू नहीं किया जाना चाहिए था, और खंड 5-ए के से जांच को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था, खंड 4 (1) अधिसूचना दिनांक 20.05.2003 और खंड 6 घोषणा दिनांक 16.06.2003 सरशियोरेराई करने के लिए प्रमाण पत्र क्षेत्राधिकार की मांग करता है। 1894 के अधिनियम की धारा 4 ने उपयुक्त सरकार या कलेक्टर को, जब भी यह प्रतीत होता है कि किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी इलाके में भूमि की आवश्यकता है, तो उस आशय की अधिसूचना जारी करने और इखंड आधिकारिक राजपत्र में और उस इलाके में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए सक्षम बनाया, जिसमें खंड कम खंड कम एक क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए; और, किसी भी भूमि के मामले को छोड़कर, जिसमें धारा 17 (4) के से राज्य सरकार के निर्देश के आधार पर, धारा 5-ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे, कलेक्टर ऐखंड इलाके में एक सुविधाजनक स्थान पर ऐसी अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना देगा।

19. 1894 के अधिनियम की धारा 5-ए आपत्तियों की सुनवाई खंड संबंधित है और, उसकी उप-धारा (1) के से, किसी भी भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जिखंड धारा 4 (1) के से अधिसूचित किया गया है, जिखंड सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक या आवश्यक होने की संभावना है, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि खंड तीस दिनों के भीतर, भूमि या उस इलाके में किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति कर सकता है, जैसा भी मामला हो।1894 के अधिनियम की धारा 5-ए (2) में यह निर्धारित किया गया है कि धारा 5-ए (1) के से प्रत्येक आपत्ति कलेक्टर को लिखित रूप में दी जाएगी, और कलेक्टर आक्षेपकर्ता को (व्यक्तिगत रूप खंड या इस ओर खंड या वकील द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा) सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी अग्रेतर की जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, उस भूमि के संबंध में उपयुक्त सरकार को एक रिपोर्ट देगा, जिसमें आपत्तियों पर उनकी सिफारिशें, उस सरकार के निर्णय के लिए उनके द्वारा आयोजित कार्यवाही के अभिलेख के साथ, शामिल हैं।1894 के अधिनियम खंड धारा 6 इस घोषणा खंड संबंधित है कि भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसखंड उप-धारा (1) में यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम के भाग VII के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जब उपयुक्त सरकार को धारा 5-ए (2) के से बनाई गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात यह संतुष्ट किया जाता है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष भूमि खंड आवश्यकता है, तो ऐसी सरकार के सचिव या ऐखंड आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत अधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के से उस आशय खंड घोषणा खंड जाएगी।

20. प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति प्रत्येक संप्रभु में निहित अधिकार है कि वह नागरिकों की सम्पति को सार्वजनिक उपयोग के लिए ले।इसे अलग तरह से कहने के लिए, संप्रभु को अपने मालिक की सहमति के बिना निजी सम्पति सहित राज्य की भूमि के किसी भी हिस्से पर अपने प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने का अधिकार है, बशर्ते कि ऐसा दावा सार्वजनिक आवश्यकता और सार्वजनिक भलाई के कारण हो।**(प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; देव शरण बनाम U.P राज्य।; राधेश्याम बनाम U.P की स्थिति। ^; देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम U.P का राज्य। और अन्य '; द्वारकादास श्रीनिवास बनाम शोलापुर कताई और बुनाई कंपनी लिमिटेड।; चिरनजीत**

लाल चौधरी बनाम भारत संघ '; और जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य 1)।हालाँकि, प्रतिष्ठित क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करते हुए, सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी सम्पति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि किसी की सम्पति को अनिवार्य रूप से लेना एक गम्भीर मामला है।**(प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; देव शरण बनाम U.P राज्य।; राधेश्याम बनाम U.P.4 राज्य और देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम U.P राज्य। और अन्य)**।राज्य द्वारा निजी सम्पति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानून, अनुचित कानून की श्रेणी में आते हैं और उनका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए **(डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल पूर्त न्यास बनाम हरियाणा राज्य 1 1; महाराष्ट्र राज्य बनाम आईडी 1)। बिलीमोरिया 1 2; प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; देव शरण बनाम U.P राज्य।; राधेश्याम बनाम स्टेट ऑफ U.P.4 और देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ U.P और अन्य**।

21. अधिनियम की धारा 4,5-ए यद्यपि 6 के अधिदेश का पालन किए बिना राज्य यद्यपि/या उसकी एजेंसियों/उपकरणों द्वारा किसी नागरिक की सम्पति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। एक सार्वजनिक उद्देश्य, चाहे वह कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो, राज्य को तत्काल प्रावधानों को लागू करने का अधिकार नहीं देता है क्योंकि इसका प्रभाव मालिक को बिना सुने सम्पति पर उसके अधिकार से वंचित करने का होता है। मात्र वास्तविक तात्कालिकता के मामले में ही राज्य तात्कालिक प्रावधानों को लागू कर सकता है और भूमि मालिक या अन्य इच्छुक व्यक्तियों को सुनने की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।**(प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; देव शरण बनाम U.P राज्य।; राधेश्याम बनाम U.P.4 राज्य और देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम U.P राज्य और अन्य**।

22. खंड 5-ए भूमि मालिक को एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है।जब सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी विशेष सम्पति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ती है, तो मालिक या सम्पति में रुचि रखने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा 5-ए के से निर्धारित समय के भीतर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का एकमात्र अधिकार होता है, और राज्य के अधिकारियों को कथित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की अनुपयुक्तता, इस तरह के अधिग्रहण खंड होने वाली गंभीर कठिनाई, सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता आदि जैखंड कारणों को निर्धारित करके उस विशेष भूमि के अधिग्रहण को छोड़ने के लिए राजी करना होता है। इसके अलावा मालिक या प्रस्तावित अधिग्रहण पर आपत्ति दर्ज करने के इच्छुक व्यक्ति को दिया गया अधिकार न मात्र एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार है, बल्कि अनिवार्य अधिग्रहण के प्रावधान को प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप भी बनाता है।**(राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य; आनंद सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1; राजा आनंद ब्रह्म शाह बनाम U.P.[1]4 राज्य; जाग राम बनाम हरियाणा राज्य 1 5; नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1 7 17; दीपक पाहवा बनाम लेफ्टिनेंट। दिल्ली के राज्यपाल 1 8; U.P का राज्य। बनाम पिस्ता देवी 1; राजस्थान आवास बोर्ड बनाम श्री किशन 2 0; चमेली सिंह बनाम स्टेट ऑफ U.P.2[1]; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम सतबीर सिंह 2 2; ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ U.P.23; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 2 4; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई 25; महादेवप्पा लाचप्पा किनागी बनाम कर्नाटक राज्य 2,6; बाबू राम बनाम हरियाणा राज्य 2,7 और टीका राम बनाम U.P.28 राज्य)**।

23. धारा 5-ए की योजना में प्राकृतिक न्याय के नियमों को शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम खंड अपनी भूमि खंड वंचित करने खंड पहले, उखंड राज्य सरकार और/या उसकी एजेंसियों/उपकरणों के भूमि के विशेष हिस्खंड का अधिग्रहण करने के निर्णय का विरोध करने का अवसर मिलना चाहिए।सुनवाई में, आक्षेपकर्ता भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को अपनी भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध अपनी सिफारिशें करने के लिए मनाने का प्रयास कर सकता है।वह यह भी बता सकते हैं कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि खंड 4 (1) के से जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है।इतना ही नहीं, वह यह दिखाने के लिए सबूत पेश कर सकता मात्र कि भूमि का एक और टुकड़ा उपलब्ध मात्र, और उसी का उपयोग विशेष परियोजना या योजना के निष्पादन के लिए किया जा सकता मात्र।**(प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2; रघबीर सिंह सहरावत बनाम हरियाणा राज्य 3; मुंशी सिंह बनाम भारत संघ 29; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1 7; श्याम नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य 3 0; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 2 4; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई और आनंद सिंह बनाम स्टेट ऑफ U.P.[1])।**

24. कलेक्टर को आक्षेपकर्ता को सुनने का उचित अवसर देना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध उसकी याचिका पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए।मात्र, उसके बाद, उसे संक्षिप्त कारणों से समर्थित सिफारिशें करनी चाहिए, कि भूमि के विशेष टुकड़े का अधिग्रहण क्यों किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और क्या आक्षेपकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकृति के योग्य है या नहीं।दूसरे शब्दों में, कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशों में भूमि मालिकों और अन्य इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दायर आपत्तियों पर मन के वस्तुनिष्ठ अनुप्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए।**(प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2; रघबीर सिंह सहरावत बनाम हरियाणा राज्य 3; मुंशी सिंह बनाम भारत संघ "; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1; श्याम नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य 3 0; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 24; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई 25 और आनंद सिंह बनाम स्टेट ऑफ U.P.[1])।**

25. तात्कालिकता खंड को लागू करने की शक्ति का उपयोग, और सरकार द्वारा धारा 5-ए के से जांच का वितरण, नियमित तरीके खंड और इस तरह धारा 5-ए के से एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार में रुचि रखने वाले मालिक या व्यक्ति को वंचित करना वैधानिक परीक्षण को पूरा नहीं कर सकता है और न ही इखंड आसानी खंड बनाए रखा जा सकता है।**(राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य; आनंद सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1; राजा आनंद ब्रह्म शाह बनाम U.P.[1]4 राज्य; जाग राम बनाम हरियाणा राज्य 1 5; नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य "; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1 7; दीपक पाहवा बनाम लेफ्टिनेंट। दिल्ली के राज्यपाल 1 8 18; U.P का राज्य। बनाम पिस्ता देवी 1; राजस्थान आवास बोर्ड बनाम श्री किशन 20; चमेली सिंह बनाम राज्य U.P.2[1] 21; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम सतबीर सिंह 2 2; ओम प्रकाश बनाम राज्य U.P.2[3]; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 2 4; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई 25; महादेवप्पा लाचप्पा किनागी बनाम कर्नाटक राज्य 2,6; बाबू राम बनाम हरियाणा राज्य 27 और टीका राम बनाम U.P.28 राज्य)।**

26. चूंकि भूमि मालिक को धारा 5-ए के से अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार दिया गया है, यह एक मूल्यवान अधिकार है, और चूंकि धारा 17 (4) के से शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप इस तरह के अधिकार खंड वंचित किया जाएगा, इसलिए यह मात्र दुर्लभ मामलों में है, जहां अधिग्रहण किसी भी विलम्ब को रोक नहीं सकता है, अगर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाए।धारा 17 (1) के से सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप खंड अधिनियम की धारा 5-ए का बहिष्कार नहीं होता है, जिसके संदर्भ में भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सकता है और अपनी आपत्तियों के समर्थन में सुनवाई का हकदार है।खंड 17 की उप-खंड (4) में "मई" शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि यह मात्र सरकार को यह निर्देश देने में सक्षम बनाता है कि खंड 5-ए के प्रावधान खंड 17 की उप-खंड (1) या (2) के से आने वाले मामलों पर लागू नहीं होंगे।दूसरे शब्दों में, खंड 17 (4) का आह्वान खंड 17 (1) के से शक्ति के प्रयोग का एक आवश्यक सहवर्ती नहीं है। **(प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; देव शरण बनाम राज्य U.P. 6; राधेश्याम बनाम राज्य U.P.4 और देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम राज्य U.P। और अन्य)।**

27. जिन परिस्थितियों में आपातकाल की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, वे खंड 17 (2) में निर्दिष्ट हैं, लेकिन खंड 17 (4) के साथ पठित खंड 17 (1) के से तात्कालिकता के आह्वान की आवश्यकता वाली परिस्थितियां स्वयं प्रावधानों में नहीं बताई गई हैं।चूंकि भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार छीन लिया जा रहा है, और कुछ प्रयासों के साथ जांच हमेशा तेजी से पूरी की जा सकती है, इसलिए तत्काल प्रावधान को संयम से लागू किया जाना चाहिए।**(राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य; आनंद सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1; राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम U.P.[1]4 राज्य; जाग राम बनाम हरियाणा राज्य 1 5 15; नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 6 16; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1; दीपक पाहवा बनाम लेफ्टिनेंट। दिल्ली के राज्यपाल 1 8 18;U.P की स्थिति। बनाम पिस्ता देवी 1 9 19; राजस्थान आवास बोर्ड बनाम श्री किशन 20; चमेली सिंह बनाम राज्य U.P. 21; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम सतबीर सिंह 2 2; ओम प्रकाश बनाम राज्य U.P। 23 "; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 24; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई 25; महादेवप्पा लाचप्पा किनागी बनाम कर्नाटक राज्य 2,6; बाबू राम बनाम हरियाणा राज्य 2,7 और टीका राम बनाम U.P.28 राज्य)**।

28. अधिनियम की धारा 17 में धारा 5-ए के से जांच को समाप्त करने की असाधारण और असाधारण शक्ति प्रदान की गई है, ऐखंड मामले में जहां भूमि पर तत्काल कब्जा करने की आवश्यकता है, या एक अप्रत्याशित आपात स्थिति में। इस तरह की शक्ति एक नियमित शक्ति नहीं है और तत्काल अधिकार की आवश्यकता वाली परिस्थितियों को छोड़कर, इखंड हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।खंड 5-ए के से जांच करने में असाधारण शक्ति के प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश खंड 17 में ही अंतर्निहित है। असाधारण शक्ति होने पर सरकार को अपने प्रयोग में उतना ही अधिक चौकस रहना चाहिए। इसलिए, सरकार को धारा 5-ए के से जांच करने खंड पहले इस पहलू पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या तात्कालिकता ऐसी प्रकृति की है जो धारा 5-ए के से संक्षिप्त जांच को समाप्त करने को उचित ठहराती है। **(राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य 3; आनंद सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1; राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम U.P.[1]4 राज्य; जाग राम बनाम हरियाणा राज्य 1 5; नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1 7; दीपक पाहवा बनाम लेफ्टिनेंट। दिल्ली के राज्यपाल 1 8 18;U.P की स्थिति। बनाम पिस्ता देवी 1 9; राजस्थान आवास बोर्ड बनाम श्री**

किशन 2 ओ; चमेली सिंह बनाम 21 का राज्य; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम सतबीर सिंह 2 2; ओम प्रकाश बनाम 2 का राज्य; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 1 4; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई 25; महादेवप्पा लाचप्पा किनागी बनाम कर्नाटक राज्य 2,6; बाबू राम बनाम हरियाणा राज्य 2,7 और टीका राम बनाम U.P.28 राज्य)।

29. जबकि खंड 17 (4) सरकार को शक्ति प्रदान करती है -यह निर्देश देते हुए कि खंड 5-ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ऐसी शक्ति का प्रयोग भूमि अधिग्रहण में तात्कालिकता के संबंध में मत के गठन के अधीन है।खंड 17 (4) के साथ पठित खंड 17 (1) राज्य को खंड 5-ए के अधिदेश का पालन किए बिना निजी सम्पति का अधिग्रहण करने की असाधारण शक्तियां प्रदान करती है। इन प्रावधानों को मात्र तभी लागू किया जा सकता है जब अधिग्रहण का उद्देश्य कुछ हफ्तों या महीनों की विलम्ब को रोक नहीं सकता है।इसलिए, धारा 5-ए के आवेदन को हटाने खंड पहले, संबंधित प्राधिकारी को पूरी तरह खंड संतुष्ट होना चाहिए कि कुछ हफ्तों या महीनों का समय, जो धारा 5-ए के से जांच करने में लिया जाने की संभावना है, पूरी संभावना में, उस सार्वजनिक उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।**(प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; देव शरण बनाम U.P राज्य।; राधेश्याम बनाम स्टेट ऑफ U.P. 1; देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ U.P। और अन्य)**।

30. अधिनियम की खंड 17 (1) और (4) के से अधिग्रहण की तात्कालिकता का प्रश्न सरकार के लिए व्यक्तिपरक संतुष्टि का विषय है और आम तौर पर, तथ्यों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर उस संतुष्टि के औचित्य की जांच करना न्यायालय के लिए खुला नहीं है।मामले के इस दृष्टिकोण में जब सरकार सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है और संतुष्ट होती है कि अधिनियम की धारा 17 (1) और (4) के से शक्तियों को लागू करने के लिए एक आपात स्थिति मौजूद है, और तदनुसार एक अधिसूचना जारी करती है, तो इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि उपयुक्त प्राधिकारी ने प्रासंगिक कारकों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है या निर्णय उचित प्राधिकारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके खंड नहीं लिया गया है।सरकार का यह निष्कर्ष कि तात्कालिकता थी, भले ही वह निर्णायक न हो, बहुत महत्वपूर्ण है।**(पहले भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य बनाम निरोध प्रकाश गंगोली और अन्य 3-1)।**

31. सरकार को इस बात पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या तात्कालिकता ऐसी प्रकृति की है जो खंड 5-ए के से जांच के वितरण को आवश्यक बनाती है। **(राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य 1 3 13; आनंद सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1; राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम U.P.[1]4 राज्य; जाग राम बनाम हरियाणा राज्य 1 5; नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1 7; दीपक पाहवा बनाम लेफ्टिनेंट। दिल्ली के राज्यपाल 1 8; U.P का राज्य। बनाम पिस्ता देवी "; राजस्थान आवास बोर्ड बनाम श्री किशन 20 चमेली सिंह बनाम राज्य U.P.2[1]; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम सतबीर सिंह 2 2 2; ओम प्रकाश बनाम राज्य U.P.2[3]; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 2 4; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई 25; महादेवप्पा लाचप्पा किनागी बनाम कर्नाटक राज्य 2,6; बाबू राम बनाम हरियाणा राज्य 2,7 और टीका राम बनाम U.P.28 राज्य)।**हालाँकि तात्कालिकता के मुद्दे पर सरकार की संतुष्टि व्यक्तिपरक है, लेकिन यह धारा 17 (1) के से शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है, यद्यपि इखंड इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि जिस उद्देश्य के लिए निजी सम्पति का अधिग्रहण करने की मांग की गई है

वह बिल्कुल भी सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है या शक्ति का प्रयोग दुर्भावना के कारण दूषित है या संबंधित अधिकारियों ने प्रासंगिक कारकों यद्यपि अभिलेखों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। **(प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2; देव शरण बनाम U.P राज्य।; राधेश्याम बनाम U.P.4 राज्य और देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम U.P.7 राज्य)।**

32. अधिसूचना में सांविधिक वाक्यांश की पुनरावृत्ति, कि राज्य सरकार संतुष्ट है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि की तत्काल आवश्यकता है और धारा 5-ए में निहित वैधानिक लागू नहीं होगा, हालांकि शुरू में सरकार के पक्ष में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्तों को पूरा कर लिया गया है, लेकिन ऐसी धारणा उन परिस्थितियों खंड विस्थापित हो सकती है जिनका स्वयं उस उद्देश्य के साथ कोई उचित संबंध नहीं है जिसके लिए शक्ति का प्रयोग किया गया है।खंड 17 के से शक्ति के प्रयोग को चुनौती दिए जाने पर, सरकार को न्यायालय के समक्ष उचित सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए कि खंड 5-ए के से जांच के लिए मत सरकार द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री पर उचित ध्यान देने के पश्चात बनाई गई है।**(राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य "; आनंद सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1; राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम U.P.[1]4 राज्य; जाग राम बनाम हरियाणा राज्य 1 5; नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य"; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1 7; दीपक पाहवा बनाम लेफ्टिनेंट। दिल्ली के राज्यपाल 1 8; U.P का राज्य। बनाम पिस्ता देवी 1; राजस्थान आवास बोर्ड बनाम श्री किशन 2 ओ; चमेली सिंह बनाम स्टेट ऑफ U.P.2[1]; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम सतबीर सिंह 2 22; ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ U.P.23; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 2 4; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई 2 5; महादेवप्पा लाचप्पा किनागी बनाम कर्नाटक राज्य 2 6; बाबू राम बनाम हरियाणा राज्य 27 और टीका राम बनाम U.P.28 राज्य)।**

33. यह जाँचने में कि क्या सरकार वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, तात्कालिकता खंड को लागू करने और धारा 5-ए जांच को समाप्त करने में उचित थी, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब भी सरकार अपनी तात्कालिकता की शक्ति का उपयोग करना चाहती है, तो उखंड पहले यह मत बनानी होगी कि उक्त सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की तत्काल आवश्यकता है।इस तरह की मत उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भूमि के तत्काल कब्जे की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए जिसके लिए भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाना चाहिए।यदि सरकार जांच को समाप्त करने का इरादा रखती है, तो उसे इस पहलू पर अपना दिमाग लगाना होगा कि तात्कालिकता ऐसी प्रकृति की है जिससे ऐसी जांच को समाप्त करने की आवश्यकता होती है।दोहरे पहलुओं पर सरकार की संतुष्टि; (i) बताए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए भूमि के तत्काल कब्जे की आवश्यकता और (ii) तात्कालिकता ऐसी है कि जांच के वितरण की आवश्यकता होती है और खंड 17 (1) और (4) के से शक्ति के वैध प्रयोग के लिए कोई विचलन की अनुमति नहीं है।**राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य 13)।**

34. यदि खंड 17 (4) के से शक्ति का आह्वान करने वाले आदेश पर हमला किया जाता है, तो अदालतें यह जांच कर सकती हैं कि क्या उपयुक्त प्राधिकारी के पास उसके सामने सभी प्रासंगिक सामग्री थी या क्या आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया है।राज्य सरकार की मत को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि यह दिखाया जा सके कि राज्य सरकार ने इस मामले पर कभी अपना दिमाग नहीं लगाया या राज्य सरकार की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण

है।यद्यपि खंड 17 (4) से संतुष्टि व्यक्तिपरक है और न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए खुली नहीं है, सीमित आधारों को छोड़कर, संतुष्टि उपयुक्त सरकार की होनी चाहिए, और संतुष्टि तात्कालिकता के अस्तित्व के संबंध में होनी चाहिए।**(प्रथम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य बनाम निरोध प्रकाश गंगोली और अन्य 3 1; जाग राम और अन्य बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य 15)**।लेकिन ऐसे मामले में जहां तात्कालिकता के बारे में मत बनाई जाती है, जो उद्देश्य के लिए विचार नहीं करती है, ऐसे प्रशासनिक निर्णय की न्यायिक समीक्षा आवश्यक हो सकती है। **(राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य 1 3; आनंद सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1; राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम U.P.[1]4 राज्य; जाग राम बनाम हरियाणा राज्य 1 5 15; नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1 7; दीपक पाहवा बनाम लेफ्टिनेंट। दिल्ली के राज्यपाल 18 1 8;U.P की स्थिति। बनाम पिस्ता देवी "; राजस्थान आवास बोर्ड बनाम श्री किशन 20; चमेली सिंह बनाम स्टेट ऑफ U.P.2[1]1; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम सतबीर सिंह 22; ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ U.P.2[3]; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 24; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई 25; महादेवप्पा लाचप्पा किनागी बनाम कर्नाटक राज्य "; बाबू राम बनाम हरियाणा राज्य 27 और टीका राम बनाम U.P.[2]8 राज्य)**

35. प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि विषय भवन का कब्जा उनके द्वारा 1947 के अधिनियम के से 14.05.2001 पर ले लिया गया था, और तब से वे कब्जे में बने हुए हैं।इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले याचिकाकर्ता पर, रिट याचिका (एम/बी) नं। 1947 के अधिनियम के से आई. डी. 2 पर मांग को चुनौती देते हुए 2002 का 165, इस न्यायालय ने आई. डी. 1 पर एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी को या तो 10 दिनों के भीतर अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को सम्पति का कब्जा सौंपने या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के से उसी का अधिग्रहण करने का निर्देश दिया गया।रिट याचिका (एम/बी) सं. में इस न्यायालय का अंतरिम आदेश। भूमि अधिग्रहण के लिए 2002 का 165 दिनांक 06.05.2003, मात्र प्रतिवादी को 10 दिनों के भीतर 1894 अधिनियम की खंड 4 के से एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता थी।जबकि अधिसूचना, 1894 अधिनियम की धारा 4 (1) के से, इस न्यायालय के उपरोक्त अंतरिम आदेश के अनुपालन में जारी की गई थी, सरकार द्वारा तात्कालिकता खंड को लागू करने की शक्ति का प्रयोग, स्पष्ट रूप खंड, इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के कारण नहीं था, क्योंकि इस न्यायालय ने प्रतिवादी को तात्कालिकता खंड को लागू करने या धारा 5-ए जांच को समाप्त करने का निर्देश नहीं दिया था।

36. यहाँ प्रतिवादी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष तर्क दिया था, जब रिट याचिका (एम /एस) 2007 के 1131 पर सुनवाई की जा रही थी, कि इस न्यायालय के दिनांकित 06.05.2003 के अंतरिम आदेश में प्रतिवादी को विषय भूमि के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता थी; भवनों का निर्माण पहले ही किया जा चुका था; और, चूंकि इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (एम/बी) सं। 2002 का 165 अभी भी लंबित था और बाद में दिनांक 1 के आदेश द्वारा निपटाया गया था, उत्तरदाताओं के पास विषय भूमि का कब्जा लेने के लिए खंड 17 (4) के से तात्कालिक खंड का आह्वान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।हालाँकि, तथ्य यह है कि इस न्यायालय द्वारा बाद में इस तरह के आदेश को पारित किए जाने की संभावना प्रतिवादी की ओर खंड मात्र एक अनुमान थी, यद्यपि यह अपने आप में यद्यपि बिना किसी यद्यपि चीज़ के, भूमि मालिक (अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता) को भूमि

अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए के से आपत्तियाँ दायर करने के अपने मूल्यवान अधिकार खंड वंचित होने को उचित नहीं ठहराता है।

37. किसी भी स्थिति में, यह मात्र उसके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर है, क्या संबंधित अधिकारी तात्कालिकता खंड को लागू करने की आवश्यकता के बारे में मत बना सकते थे।यद्यपि प्रतिवादी को यह दिखाने के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया विद्वान था कि क्या कोई ऐसी सामग्री है जिसके आधार पर प्रतिवादी ने ऐसी मत बनाई थी, उत्तराखंड राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जोशी ने हमें सूचित किया कि सरकार के पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।अतः यह स्पष्ट है कि तात्कालिकता खंड को लागू करने के लिए मत का गठन सरकार के समक्ष रखी गई किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं था।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मात्र "तात्कालिकता" शब्द का उपयोग भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5-ए के से आपत्तियां दर्ज करने के अपने अधिकार खंड वंचित होने को उचित नहीं ठहराएगा क्योंकि यह मात्र वास्तविक तात्कालिकता के मामलों में ही है, जो 1894 अधिनियम की धारा 5-ए के से जांच के भीतर वितरित करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

38. जबकि श्री जोशी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, अपनी प्रस्तुतीकरण में उचित हैं कि संस्थागत उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण, खंड 4 के अर्थ के भीतर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण है, लेकिन यह अपने आप में, खंड 17 (1) और/या 17 (4) के से सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग को उचित नहीं ठहराता है।**(प्रभावती और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; देव शरण बनाम U.P.º राज्य; राधेश्याम बनाम U.P.4 राज्य और देवेंद्र कुमार त्यागी और अन्य बनाम U.P राज्य और अन्य**)।यह प्रस्तुतीकरण कि 1947 के अधिनियम के संदर्भ में और उसके बाद खंड, जब धारा 4 (1) अधिसूचना जारी की गई थी, तब धारा 17 (4) के से तात्कालिक खंड को लागू करना आवश्यक हो गया था, तब खंड विषय सम्पति का निरंतर कब्जा स्वीकार करने योग्य नहीं है।पूर्व-अधिसूचना या अधिसूचना के बाद की विलम्ब का तात्कालिकता शक्ति के आह्वान के प्रश्न खंड कोई संबंध नहीं है, विशेष रूप खंड ऐसी स्थिति में जहां उपयुक्त सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि तात्कालिकता ऐसी प्रकृति की थी जिसके कारण धारा 5-ए के से जांच को समाप्त करना आवश्यक हो गया था। **(राम धारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट बनाम भारत संघ और अन्य; आनंद सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 1; राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम 14 का राज्य; जाग राम बनाम हरियाणा राज्य 1 5; नारायण गोविंद गावटे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1; पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह 1; दीपक पाहवा बनाम लेफ्टिनेंट। दिल्ली के राज्यपाल 18 1 8;U.P की स्थिति। बनाम पिस्ता देवी 1 9 19; राजस्थान आवास बोर्ड बनाम श्री किशन 20; चमेली सिंह बनाम 21 का राज्य; मेरठ विकास प्राधिकरण बनाम सतबीर सिंह 2 2; ओम प्रकाश बनाम 23 का राज्य; भारत संघ बनाम मुकेश हंस 24; हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लि. बनाम डेरियस शापुर चेनाई 25; महादेवप्पा लाचप्पा किनागी बनाम कर्नाटक राज्य 2,6; बाबू राम बनाम हरियाणा राज्य 2,7 और टीका राम बनाम U.P.28 राज्य)।**जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश में राज्य को अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता थी, जिसका मात्र यह अर्थ था कि 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के से एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता थी।न्यायालय के किसी भी आदेश की अनुपस्थिति में में, प्रतिवादी को 1894 के अधिनियम की खंड 5-ए के से या तो जांच को समाप्त करने या तात्कालिकता खंड को लागू करने की अनुमति देते हुए, केवल यह तथ्य कि इस न्यायालय ने 1894 के अधिनियम के से अधिग्रहित की जाने वाली विषय भूमि का निर्देश दिया था,

प्रतिवादी को 1894 के अधिनियम की खंड 17 (4) के से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5-ए जांच को समाप्त करने के लिए उचित नहीं ठहराएगा।

39. अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जोशी का यह प्रस्तुतीकरण कि चूंकि प्रतिवादी ने 1947 के अधिनियम के से विषय भूमि पर कब्जा कर लिया था और चूंकि उसमें निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी, इसविद्वान पहले के अवैध कब्जे को वैध बनाने के विद्वान तत्काल खंड को लागू करने की तत्काल आवश्यकता थी, भी मान्य नहीं है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी ने 1947 के अधिनियम के से विषय भूमि का कब्जा 1894 के अधिनियम की धारा 4 (1) के से अधिसूचना जारी होने खंड दो साल खंड अधिक समय पहले 20.05.2003 पर ले लिया था।चूंकि प्रतिवादी ने तब से इमारत पर कब्जा बनाए रखा है, इसलिए अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता मात्र सक्षम क्षेत्राधिकार के सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने के अपने सामान्य कानून उपचार का लाभ उठाकर प्रतिवादी को वहां से बेदखल कर सकता था।1947 के अधिनियम के से विषय भूमि का कब्जा बनाए रखने के बाद और उसके बाद, दो साल खंड अधिक की अवधि के लिए, प्रतिवादी विषय भूमि के अवैध कब्जे को बनाए रखने में अपने स्वयं के अवैध कार्य का लाभ यह तर्क देने के लिए नहीं ले सकते हैं कि वे अपने कब्जे को वैध बनाने के लिए 1894 के अधिनियम की धारा 17 (4) का आह्वान करने में उचित थे।

40. **प्रथम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य बनाम निरोध प्रकाश गंगोली और अन्य 3 1 मामले में**, जिस पर श्री द्वारा अवलम्ब रखी गई है। जोशी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, ने प्रतिवादी की ओर खंड आग्रह प्रश्नया प्रश्न चूंप्रश्न विचाराधीन परिसर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के कब्जे में बना रहा, इसलिए धारा 17 के से विशेष शक्तियों का आह्वान प्रश्नया विद्वान और धारा 5-ए के से आपत्तियां दर्ज करने के लिए भूमि मालिकों का एक मूल्यवान अधिकार छीन नहीं लिया जा सकता था; धारा 5-ए के से जांच के साथ धारा 17 के से शक्ति, जहां भूमि का तत्काल कब्जा लेने की तात्कालिकता मौजूद है, वहां लागू की जा सकती है, लेप्रश्नन जहां कब्जा अधिग्रहण प्राधिकरण के पास है, वहां कोई तात्कालिकता मौजूद नहीं हो सकती है और इसलिए, अभ्यास प्रश्नया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में, **बलवंत नारायण भागड़े बनाम M.D भागवत और अन्य 32** पर अवलम्ब रखी गई थी

41. यही तथ्यात्मक मैट्रिक्स है कि सर्वोच्च न्यायालय ने **निरोध प्रकाश गंगोली और अन्य 31** मामलों में यह अभिनिर्धारित किया कि विषय परिसर को अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों के से अधिग्रहित किया गया था और 1993 खंड उक्त अधिनियम की धारा 10 बी के संचालन द्वारा मांग खंड मुक्त कर दिया गया था; भले ही परिसर मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन ऐसा व्यवसाय न तो मालिक के रूप में था और न ही कानून की नजर में वैध था; वैध अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, और क्योंकि उद्देश्य एक सार्वजनिक उद्देश्य था, राज्य सरकार दिसंबर, 1982 खंड प्रयास कर रही थी, और अदालत के हस्तक्षेप के कारण इसका प्रत्येक प्रयास विफल रहा था; यह इस संदर्भ में है कि शक्ति के प्रयोग की वैधता

42. सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ, **निरोध प्रकाश गंगोली और अन्य 31** में, न्यायालय द्वारा बार-बार हस्तक्षेप के संदर्भ में की गई थीं, जिससे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए विषय भूमि का अधिग्रहण करने के अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को विफल कर दिया गया था।उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप खंड कहा है कि धारा 17 के से शक्तियों के प्रयोग की वैधता की जांच इस संदर्भ में की जानी चाहिए कि राज्य सरकार ने दिसंबर, 1982 खंड भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास किया है और न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण इसके प्रत्येक प्रयास विफल हो गए

हैं।वर्तमान मामले में 1894 के अधिनियम की खंड 4 (1) के से प्रतिवादी द्वारा जारी अधिसूचना को इस न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया गया है।किसी भी स्थिति में, 1894 के अधिनियम की धारा 17 (4) के से शक्ति के प्रयोग के लिए सरकार के समक्ष कोई सामग्री रखे जाने की अनुपस्थिति में में, इस तरह की शक्ति का प्रयोग विवेक के गैर-प्रयोग खंड पीड़ित था और दूषित हो गया था।

43. 1894 अधिनियम की खंड 4 (1) के से अधिसूचना 20.05.2003 पर जारी की गई थी और खंड 6 के से घोषणा 16.06.2003 पर जारी की गई थी।अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता ने धारा 4 (1) अधिसूचना और धारा 6 घोषणा दोनों पर रिट याचिका (एम/बी) सं. 17.02.2004 पर पुरस्कार दिए जाने खंड पहले 04.07.2003 पर 2003 का 607।लिखित याचिका (एम/बी) सं। 2003 के 607 को बाद में रिट याचिका (एम/एस) सं। 2007 का 1131।यद्यपि हम संतुष्ट हैं कि प्रतिवादी को 1894 के अधिनियम की खंड 5-ए के से जांच के लिए कुछ महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता था, और अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को अधिग्रहण पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए था, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि प्रतिवादी ने <आईडी1> पर एक पुरस्कार पारित किया था, और अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता ने न तो पुरस्कार की वैधता पर सवाल उठाया है और न ही उन्होंने 1894 के अधिनियम की खंड 18 के से न्यायालय में संदर्भ की मांग की है।

44. अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता की ओर खंड उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री A.S रावत ने कहा कि अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता ने धारा 4 (1) की अधिसूचना और धारा 6 की प्रस्तुतीकरण की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि धारा 5-ए की जांच नहीं की गई थी, और एक बार जब न्यायालय यह मान लेता है कि धारा 5-ए की जांच करने में विफलता अवैध है, तो बाद के पुरस्कार सहित सभी कार्यवाही को निरर्थक नहीं कहा जा सकता है।हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रतिवादी ने भूमि पर कब्जा करने के पश्चात यद्यपि एक पुरस्कार पारित की अनुपस्थिति में पहले यद्यपि बाद में, रुपये से अधिक की राशि खर्च की है। विषय भूमि पर सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए 6.00 करोड़, यद्यपि इस अवधि में (ID2 पर पुरस्कार पारित होने के लगभग 15 साल बाद), पुरस्कार को रद्द घोषित करना पूरी तरह से असमान होगा, भले ही इसके लिए कोई चुनौती न हो।

45. **न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम हरकिशन (मृत) एल. आर. के माध्यम खंड और अन्य 3 3,** जिन पर श्री अन्यशी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, द्वारा अवलम्ब रखी गई है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिकाओं के दूसरे दौर में, उन्होंने मात्र 3 दिसंबर, 1999 के कार्यालय आदेश को चुनौती देने का विकल्प चुना, जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 48 के से उनका अभ्यावेदन विलम्ब कर दिया विद्वान था; और उन्हें इस आधार पर पुरस्कार की वैधता को चुनौती देने का कभी एहसास नहीं हुआ कि यह सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर पारित नहीं किया विद्वान था; मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में भी, प्रतिवादी ने अपने प्रयास में विफल रहे थे, जितना कि सर्वोच्च न्यायालय ने 12 मार्च, 2003 के अपने फैसले के माध्यम खंड 3 दिसंबर, 1999 के अस्वीकृति आदेश के लिए अपनी अभेद्यता रखी थी; उस समय, भूमि का कब्जा था। वी.उत्तर प्रदेश राज्य & Ors.[3]4 34; अन्य अवध बिहारी यादव & अन्य। वी.बिहार राज्य और अन्य 3 5.

46. उपरोक्त निर्णय से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामले में, पुरस्सेर मात्र इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिसे विचाराधीनता रहने के दौरान पारित किया गया था,

जिसमें खंड 4 (1) अधिसूचना और खंड 6 की घोषणा की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि खंड 5-ए की जांच करने में विफलता घातक थी।

47. फिर वह राहत क्या होनी चाहिए जो अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को हमारे इस निर्णय के परिणामस्वरूप दी जानी चाहिए कि प्रतिवादी द्वारा तात्कालिकता खंड का आह्वान मन का उपयोग न करने खंड पीड़ित था, और उन्होंने धारा 5-ए जांच के साथ अवैध रूप खंड कार्य किया था?इस प्रश्न का उत्तर देने में, प्रतिवादी द्वारा 1894 अधिनियम की धारा 17 (4) के से शक्तियों का प्रयोग करने में अवैधता को पिछले लगभग 15 वर्षों खंड रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान पारित किए गए पुरस्कार पर सवाल उठाने में अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता की विफलता के साथ तौला जाना चाहिए।

48. इस संदर्भ में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भूमि अधिग्रहण में दावेदारों की ओर से अतिरिक्त सतर्कता अपनाने में चूक हो सकती है, लेकिन इसका उपयोग उन्हें लापरवाही या वास्तविक अभाव के रूप में चित्रित करने के लिए एक आधार के रूप में करने की आवश्यकता नहीं है।समानताओं को उस अवधि के लिए अपीलार्थियों के हित को अस्वीकार करके संतुलित किया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था।अपीलार्थियों के मूल अधिकारों को स्व-अधिरोपित सीमाओं के बारे में अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर तकनीकी आधार पर पराजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के मामले में, न्यायालय का दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिए न कि पांडित्यपूर्ण।**(के. सुब्बारायुडू और अन्य बनाम विशेष उप कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) 3 6; धीरज सिंह (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 3 7 37 द्वारा से)।धीरज सिंह 3 7 और के. सुब्बारायुडू 3** दोनों में, सर्वोच्च न्यायालय ने संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार के विरुद्ध अपील करने में विलम्ब की अवधि के लिए अपीलकर्ताओं को ब्याज देने से इनकार कर दिया।

49. धारा 5-ए जांच करने और अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को अपनी आपत्तियां दायर करने का अवसर देने में प्रतिवादी की विफलता के लिए पुरस्कार को दरकिनार करना उचित नहीं होगा क्योंकि इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के से नए सिरे खंड भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करनी होगी। ऐसी परिस्थितियों में, पुरस्कार को अपास्त रखना पूरी तरह से असमान होगा, क्योंकि इन रिट कार्यवाही में इसे चुनौती भी नहीं दी गई है।यद्यपि हम संतुष्ट हैं कि हमारी इस धारणा पर कि धारा 17 (4) के से सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग अवैध है, अपीलकर्ता रिट याचिकाकर्ता को कम खंड कम 1894 के अधिनियम के से मुआवजे में वृद्धि की मांग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता ने 1894 के अधिनियम की धारा 18 के से मात्र इस न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका विचाराधीनता होने के कारण संदर्भ नहीं मांगा था, और ऐसा न हो कि धारा 6 की घोषणा के लिए उनकी चुनौती की वैधता, इस आधार पर खारिज कर दी गई है कि प्रतिवादी धारा 5-ए की जांच करने में विफल रहे थे।न्यायाधीश के अंत को पूरा किया जाएगा यदि अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को 1894 अधिनियम की खंड 18 के से सक्षम प्राधिकारी को दीवानी न्यायाधीशालय में संदर्भ की मांग करने के लिए

आवेदन करने की अनुमति दी जाती है।यदि आज खंड चार सप्ताह के भीतर ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी, रिट याचिका विचाराधीनता होने और इस न्यायालय के समक्ष विशेष अपील के कारण हुई विलम्ब को ध्यान में रखे बिना, मामले को सक्षम दीवानी न्यायालय को भेजेगा, जो तब 1894 के अधिनियम के से मुआवजे में वृद्धि के लिए अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा। चूँकि अपीलार्थी रिट याचिकाकर्ता भी पुरस्कार पर सवाल नहीं उठा रहा है, या 1894 अधिनियम की धारा 18 के से संदर्भ की मांग करने में गलत रहा है, हम उच्चतम न्यायालय द्वारा **धीरज सिंह (मृत) मामले में कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 3 7 और के. सुब्बारायुडू और अन्य बनाम विशेष उप-कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) 36** द्वारा खंड घोषित कानून का पालन करते हुए निर्देश देते हैं कि संदर्भ न्यायालय उन्हें पुरस्कार की तिथि खंड उस तिथि तक ब्याज नहीं देगा जब तक कि अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता 1894 अधिनियम की धारा 18 के से कलेक्टर को आवेदन नहीं करता है, भले ही यह संतुष्ट हो कि मुआवजे का भुगतान, अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता को पहले किया गया था, वृद्धि की आवश्यकता है।

50. अपील के से आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाता है, और विशेष अपील का निपटारा किया जाता है।यद्यपि परिस्थितियों में, बिना किसी लागत के।

(आलोक सिंह, जे.) (रमेश रंगनाथन, C.J)

08.01.2019

08.01.2019

राहुल